

सीमांत क्षेत्रों में जनसंख्या असंतुलन की होगी पड़ताल

समस्या के स्थायी समाधान के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित, एक वर्ष के भीतर देगी रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस पीपी नावलेकर होंगे समिति के अध्यक्ष

पूर्व आइएएस दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आइपीएस बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री शमिका रवि सदस्य

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

देश में अवैध घुसपैठ और उसके कारण कई भागों, खासकर सीमांत क्षेत्रों में हो रहे जनसांख्यिकी परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता में गठित यह समिति एक वर्ष में जनसांख्यिकी परिवर्तन के कारणों का अध्ययन कर उससे निपटने के स्थायी उपायों पर रिपोर्ट देगी। जरूरत पड़ने पर इसका कार्यकाल छह माह बढ़ाया जा सकता है। पीएम नरेन्द्र मोदी ने गत वर्ष 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति के गठन की घोषणा की थी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, घुसपैठ और अन्य कारणों से असामान्य जनसांख्यिकी परिवर्तन किसी भी राष्ट्र के वर्तमान एवं भविष्य के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। उनके अनुसार, समिति पूरे भारत में घुसपैठ और असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकी परिवर्तनों के कारणों का व्यापक मूल्यांकन कर सुनियोजित व समयबद्ध समाधान पेश करेगी। कहा, जनसांख्यिकी परिवर्तन देश की संप्रभुता के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, सामाजिक संरचना में गंभीर बदलाव व जनजातीय समाज के संरक्षण से जुड़ी बड़ी समस्या है। समिति धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर



बंगाल के वशीरहाट स्थित हाकिमपुर चेकपोस्ट पर मंगलवार को बांग्लादेश जाने के इंटरजार में खड़े घुसपैठिए।

एनआइ

समिति इन आठ मुद्दों पर करेगी काम

- अवैध अप्रवास सहित जनसांख्यिकीय परिवर्तनों से उत्पन्न चुनौतियों पर व्यापक विचार करना।
- ऐसे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के संभावित कारणों का अध्ययन करना, जैसे- सीमा पार गतिविधियां (अवैध अप्रवास सहित), आर्थिक अवसर और अन्य सामाजिक-पर्यावरणीय कारक।
- इन परिवर्तनों के पीछे के अंतर्निहित कारकों की पहचान करना; जिसमें अवैध अप्रवास, असामान्य बसावट पैटर्न और नियोजित प्रवास शामिल हैं।
- धार्मिक या सामाजिक समुदायों के स्तर पर संरचनात्मक जनसंख्या परिवर्तनों का विश्लेषण करना, विशेष रूप से समान रुझानों से अलग होने पर।
- देश में पहले से ही रहने वाले अवैध अप्रवासियों की कानूनी, निष्पक्ष और समयबद्ध पहचान; हिरास्त और निर्वासन के लिए एक सुव्यवस्थित और स्थायी परिचालन प्रणाली की सिफारिश करना।

- ऐसे रुझानों की निरंतर निगरानी के लिए सीमा प्रबंधन, जनसंख्या स्थिरीकरण और पहचान प्रणालियों को मजबूत करने के लिए एक उपयुक्त संस्थागत तंत्र की सिफारिश करना।
- अवैध अप्रवास और परिणामी जनसांख्यिकीय असंतुलन से संबंधित मामलों में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए एक व्यापक नीतिगत ढांचा प्रस्तावित करना।
- समिति जनसांख्यिकीय परिवर्तनों से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए किसी अन्य उपाय, जिसे वह उचित समझे, की सिफारिश कर सकती है।

पर भी असामान्य जनसंख्या परिवर्तन के पैटर्न का भी विश्लेषण करेगी।

समिति के सदस्य : पूर्व आइएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व

आइपीएस बालाजी श्रीवास्तव और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की सदस्य डा. शमिका रवि को समिति का सदस्य बनाया गया है। भारत

के जनगणना आयुक्त को भी समिति में शामिल किया गया है। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव (विदेशी नागरिक) समिति के सदस्य सचिव होंगे। गृह

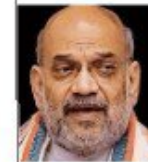
मोदी ने कहा था...

आज मैं देश को एक चिंता और एक चुनौती के बारे में आगाह करना चाहता हूँ। एक साजिश के तहत देश की जनसांख्यिकी को बदला जा रहा है। नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं। ये



'घुसपैठिए' मेरे देश के युवाओं की रोजी-रोटी छीन रहे हैं, ये मेरे देश की बहनो और बेटियों को निशाना बना रहे हैं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये 'घुसपैठिए' भोले-भाले आदिवासियों को गुमराह कर रहे हैं और उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। जब जनसांख्यिकीय बदलाव होते हैं, खासकर सीमावर्ती इलाकों में, तो वे राष्ट्रीय सुरक्षा का

समिति पूरे भारत में अवैध घुसपैठ और असामान्य कारणों से हो रहे



जनसांख्यिकी परिवर्तनों के कारणों का व्यापक मूल्यांकन कर सुनियोजित और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या परिवर्तन के पैटर्न का भी विश्लेषण करेगी।

- अमित शह, केंद्रीय गृह मंत्री

मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, गठन के साथ ही समिति काम शुरू कर देगी।

(बंगाल में श्रेलिंग सेंटर की घोषणा के बाद सीमा पर बढ़ी हलचल: पेज-5)

बदलनी होगी उर्वरक उपयोग की रीति-नीति



आदित्य सिन्हा

उर्वरक सब्सिडी से उपजी समस्या का एक पहलू यह भी है कि सस्ती दरों पर मिले उर्वरक का किसान आवश्यकता से अधिक उपयोग करते हैं

प्रधानमंत्री मोदी ने बीते दिनों किसानों से आह्वान किया कि वे यूरिया और डीएपी जैसे रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कम से कम आधे कौं कटौती करें और अधिक से अधिक प्राकृतिक खेती करें। इस अपील के पर्यावरणीय ही नहीं, अपितु आर्थिक निहितार्थ भी हैं। भारत उर्वरकों पर भारी-भरकम राशि खर्च करता है और उसकी बहुलता खरीदारी विदेश से होती है। अभी विदेशी उर्वरक की खरीद मुश्किल और बेहद महंगी हो गई है, जिससे संकट कहीं ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए उर्वरकों के उपयोग का रवैया बदलना ही होगा।

भारत में किसान 45 किग्रा यूरिया का एक बैग 266 रुपये में खरीदता है, जबकि इसकी वास्तविक कीमत करीब 4,000 रुपये होती है। इसकी बिक्री पर होने वाले घाटे को भरपाई सरकार खुद करती है। इसी सरकारी सब्सिडी के चलते किसान के लिए खेती की लागत नियंत्रित रहती है। मुश्किल यह है कि सरकार के लिए अब यह खर्च इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसे वहन करना काबू से बाहर जा रहा है। वित्त वर्ष 2026-27 में सरकार ने 1.7 लाख करोड़ रुपये केवल उर्वरक सब्सिडी पर खर्च किए और इस साल यह खर्च कहीं ज्यादा बढ़ेगा। इतनी विशाल राशि से तो बड़े

पैमाने पर सिंचाई के लिए नहर, ग्रामीण सड़कों या स्कूलों का निर्माण किया जा सकता है। पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग और उर्वरक आपूर्ति के एक प्रमुख जलमार्ग होर्मुज में गतिरोध से चरमराई आपूर्ति के चलते भारत को इस समय विदेशी बाजार से 959 डॉलर प्रति टन की दर पर यूरिया खरीदना पड़ रहा है। ये दरें दो महीनों के अंतराल में लगभग दोगुनी बढ़ गई हैं। इस दर पर 25 लाख टन का कोई ऑर्डर एक ही झटके में साल भर के आयात का एक चौथाई हिस्सा खर्च कर देगा।

सब्सिडी से उपजी समस्या का एक पहलू यह भी है कि सस्ता मिलने से किसान उर्वरकों का आवश्यकता से अधिक उपयोग करते हैं। विज्ञानियों की अनुशांसा के अनुसार तीन मुख्य पादप पोषक तत्वों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का 4:2:1 के अनुपात में ही संतुलित उपयोग करना चाहिए। जबकि भारतीय खेतों में यह अनुपात सामान्यतः 11:4:1 का होता है। चानी यूरिया का अतिरिक्त और शेष का अत्यल्प उपयोग। केंद्रीय उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा का भी कहना है कि जहां दो बैग की जरूरत है, वहां किसान चार बैग उर्वरक उपयोग करते हैं। यह अतिरिक्त यूरिया फसल के लिए उपयोगी नहीं होता। इसका एक तिहाई हिस्सा ही पौधे अवशोषित कर



अवधेश राजपूत

पाते हैं और शेष या तो घातक ग्रीनहाउस गैसों के रूप में उत्सर्जित हो जाता है या भूजल में घुल जाता है। सस्ता यूरिया मिट्टी के साथ ही पानी को भी दूषित कर रहा है।

एक समस्या रिसाव की है। जब कोई वस्तु वास्तविक मूल्य से कम पर बिकती है तो उसके दुरुपयोग की आशंका कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। सरकारी आकलन के अनुसार करीब 20 प्रतिशत उर्वरक बैग कालाबाजारी की भेंट चढ़ जाते हैं। ये बैग या तो उन उद्योगों तक पहुंचाए जाते हैं, जहां यूरिया का उपयोग एक औद्योगिक रसायन के रूप में होता है या फिर तस्करी के जरिये विदेश, जहां उनकी ऊंची कीमत मिलती है। इस तरह किसानों के लिए खर्च की जाने वाली राशि गलत हाथों में पहुंचती है।

इस दिशा में सुधार के उपायों की बात करें तो एक उपाय किसानों को सीधे नकदी प्रदान करने का हो सकता है। उर्वरक बैग को सस्ता बेचने के बजाय सरकार जोत के आकार और भूमि की गुणवत्ता के आधार पर यूरिया की आवश्यकता को चिह्नित करते हुए

आवश्यक राशि सीधे किसानों के खाते में भेजे। आधार पहचान पत्र, सभी तक बैंकिंग की पहुंच और मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सहायता से इसे सहजता के साथ संभव बनाया जा सकता है। इससे किसानों को अपेक्षित सहायता भी मिलती रहेगी और रिसाव भी रुकेगा। दूसरा उपाय यह हो सकता है कि यूरिया की कीमत को उसके वास्तविक स्तर तक बढ़ने दिया जाए। 266 रुपये और 4,000 रुपये के बीच का यह भारी-भरकम अंतर ही लोगों को यूरिया की कालाबाजारी के लिए उकसाता है। कीमतें बढ़ने से मुनाफ़ाखोरी की प्रवृत्ति पर लगाम लगेगी तो किसान भी किफायत से इसके उपयोग को उन्मुख होंगे। वास्तविक लाभार्थी के रूप में किसानों के खातों में मिलने वाली नकदी से खरीद में समस्या भी नहीं आएगी। इस क्रम में तीसरा उपाय यह हो सकता है कि यूरिया को भी अन्य उर्वरकों की दृष्टि से देखा जाए।

वर्ष 2010 से फास्फोरस और पोटेशियम उर्वरकों को अपेक्षाकृत अधिक न्यायसंगत व्यवस्था के तहत नियंत्रित

किया जा रहा है, जिसमें सब्सिडी का पहलू इस बात पर निर्भर करता है कि उस बैग में पोषक तत्व की मात्रा कितनी है। यूरिया को इस व्यवस्था से बाहर रखा गया। यही एकमात्र अपवाद था, जिसने किसानों को यूरिया का आवश्यकता से अधिक उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। यूरिया को भी इसी समान व्यवस्था के दायरे में लाने से मिट्टी के पोषण संतुलन को फिर से बहाल करने में भी मदद मिलेगी। चौथा उपाय कारगर तरीकों की सराहना से जुड़ा है। अभी सरकार केवल परंपरिक दानेदार यूरिया पर ही सब्सिडी देती है, भले ही पत्तियों पर छिड़का जाने वाला तरल यूरिया उसकी तुलना में कहीं बेहतर तरीके से अवशोषित होता हो और उसकी बर्बादी भी बहुत कम होती हो। ऐसे में, सब्सिडी के लिए किसी पुराने या परंपरिक परिपाटी के बजाय प्रभावी नई परंपरा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

पिछले 40 वर्षों से विशेषज्ञ समितियां इसी प्रकार के सुधारों की सिफारिश करती रही हैं, लेकिन उन्हें उपेक्षित ही किया जाता रहा है। ऐसा इसलिए, क्योंकि यदि एक बार कोई वस्तु सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जाने लगे तो उस व्यवस्था को पलटना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि हाल के संकट ने इससे जुड़ा पूरा गणित ही बिगाड़ दिया है। याद रहे कि जब कोई उत्पाद दुर्लभ और महंग हो जाता है तो उसके उपयोग की रणनीति बदलनी ही पड़ती है। प्रधानमंत्री ने इस समस्या को रेखांकित कर दिया है और उसके समाधान की राह भी सामने है, लेकिन यह राह बहुत लंबे समय तक खुली नहीं रहेगी।

(लेखक लोक-नीति विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

सुविधा • सीएम ने स्वास्थ्य, शिक्षा, पीएचईडी व पथ निर्माण विभाग की समीक्षा की, कई निर्देश दिए; कहा- जिला मुख्यालय फोर लेन से जुड़ें ऐसा इंतजाम करें कि दूसरे राज्यों के बच्चे बिहार में पढ़ने आएँ : सम्राट

पॉलिटिकल रिपोर्ट | पटना

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को बैंक टू बैंक 4 विभागों (स्वास्थ्य, शिक्षा, पीएचईडी, पथ निर्माण) की समीक्षा की। कई निर्देश दिए। बोले- सभी जिला मुख्यालय 4 लेन से कनेक्ट किए जाएं। पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड में मेडिकल कॉलेजों का विकास हो। ऐसा इंतजाम हो कि दूसरे राज्यों के बच्चे बिहार में पढ़ने आएँ। 1 जुलाई से उन 211 प्रखंडों के डिग्री कॉलेजों में पढ़ाई शुरू हो, जहां ये कॉलेज नहीं हैं। 'हर घर नल का जल' के तहत जलापूर्ति का समय 2 घंटा बढ़ाया जाए। पेश हैं विभागों को दिए गए उनके खास निर्देश...

निर्देश दिया... 1 जुलाई से 211 प्रखंडों के डिग्री कॉलेजों में पढ़ाई शुरू हो, पीपीपी मोड में मेडिकल कॉलेजों का विकास हो

पथ निर्माण विभाग



- कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल का काम जुलाई 2026 के पहले हफ्ते में पूरा हो।
- एक्सप्रेस वे, एनएच, एसएच का काम तेजी से पूरा हो,

गुणवत्ता का खयाल रहे।

- पर्यटन स्थल, सांस्कृतिक विरासत, औद्योगिक कॉरिडोर, विशेष कृषि उत्पादन क्षेत्र, महत्वपूर्ण बाजारों को बेहतर कनेक्टिविटी मिले।
- पुलों की मजबूती की जांच लगातार हो।

स्वास्थ्य विभाग



- अस्पतालों में मरीजों के बेहतर इलाज में कोई कोताही न हो।
- अनुमंडल व जिला अस्पतालों द्वारा दूसरे

अस्पतालों में अनावश्यक रूप से रेफर करने की व्यवस्था 15 अगस्त तक बंद हो।

- डीएम इसकी मॉनीटरिंग करें।
- निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल का निर्माण तेजी से पूरा हो।

शिक्षा विभाग



- देश के टॉप 10 विश्वविद्यालयों से बिहार के कॉलेजों को जोड़ें, ताकि बाहर के भी बच्चे बिहार में पढ़ने आएँ
- डिग्री कॉलेजों के लिए जो

जमीन देंगे, उनके नाम पर कॉलेज होगा

- विक्रमशिला विश्वविद्यालय पुनर्स्थापित होगा। केंद्र सरकार को जमीन जल्द दी जाएगी
- ओपेन यूनिवर्सिटी की संख्या बढ़ाई जाए
- सभी रिसर्च सेंटर और व्यवस्थित हों।

लोक स्वास्थ्य अभिव्यंजन विभाग



- हर घर नल का जल के तहत निर्बाध आपूर्ति की गारंटी हो
- पेयजल आपूर्ति का समय सुबह-शाम एक-एक घंटा बढ़ाएं
- शिकायतों का तुरंत समाधान

हो, इसमें एआई का उपयोग हो

- हरेक दो-तीन महीने पर पंचायतवार जांच हो
- जहां जरूरत है वहां 30 जून के पहले नया चापाकल लगाएं। भू-जल संरक्षण की योजनाएं बेहतर ढंग से क्रियान्वित हों।

India, U.S. draw up deal on rare earth elements

Framework follows growing concerns over China's export controls of strategic metals; Australia, Japan join fellow Quad members in separate framework among the grouping on critical minerals

Kallol Bhattacharjee
NEW DELHI

On the sidelines of the 11th Quad Foreign Ministers' Meeting (FMM), India and the United States on Tuesday firmed up an important framework for cooperation in ensuring steady supplies of critical minerals, in a move that follows growing concerns over China's export controls of rare earth minerals and strategic metals vital for technology supply chains.

"The Framework aims to deepen India-U.S. cooperation across the critical minerals and rare earths supply chain, including mining, processing, recycling and related investments. It seeks to strengthen resilient and diversified supply chains,

Rare deal

The framework comes amid shortfall of critical metals in global markets after China imposed export curbs on rare earth elements



Mining strategy: The agreement follows continued India-U.S. engagements, including India becoming a signatory to the U.S.-led Pax Silica initiative. REUTERS

Framework seeks to:

- Implement **effective management** of critical minerals and rare earths scrap
- Strengthen resilient and **diversified supply chains**
- Promote **collaboration in financing**

while promoting collaboration in financing and effective management of critical minerals and rare earths scrap," said an announcement on the "Framework" titled "Securing of supply in the mining and processing of critical minerals and rare earths".

The understanding between India and the U.S. has been under consideration at least since Prime Minister Narendra Modi's visit to Washington in February 2025, when secure supply routes for critical minerals were considered a "shared strategic

priority", said a official press note.

A separate framework on critical minerals was also signed among the four Quad nations – Australia, India, Japan and the United States – which aims at mobilising around \$20 billion in government and private-sector support to establish stable supply chains for critical minerals.

The initiatives aim at dealing with the shortfall of critical metals in global markets that intensified after China imposed export controls on rare earth elements in 2025, after the U.S.'s imposition of tariffs on a large number of partner countries.

CONTINUED ON
» **PAGE 10**
EDITORIAL
» **PAGE 6**

India's energy strategy needs price correction

The Strait of Hormuz is no longer just a geopolitical flashpoint; it has become the fault line of the global energy economy. As tensions in West Asia continue to disrupt shipping through one of the world's most critical maritime corridors, countries across the globe are confronting a harsh reality: energy security is now inseparable from geopolitics. For India, which depends on imports for the overwhelming majority of its crude oil needs, the crisis has exposed both the strength of recent policy interventions and the limits of shielding consumers indefinitely from market realities.

The immediate impact of the conflict has been visible in global crude markets. Brent prices have surged sharply amid fears of prolonged disruption to Gulf supplies, while freight costs and marine insurance premiums have climbed to multi-year highs. Shipping routes are being diverted around the Cape of Good Hope, extending delivery timelines by weeks and significantly increasing transportation expenses. Global gas markets, too, remain under pressure following disruptions linked to the shutdown of key liquefied natural gas export infrastructure in Qatar. Despite this turbulence, the crisis has not hit Indian consumers as ferociously as it should be so far. Petrol and diesel prices at Indian fuel pumps have remained relatively stable, hovering near ₹95 per litre in many cities, even as fuel prices in several advanced economies rose steeply, by about 25% on average. Petrol prices in Germany and the United Kingdom have crossed the equivalent of roughly ₹220 and ₹204 per litre, respectively, while Hong Kong continues to record some of the world's highest fuel prices at nearly ₹291 per litre. This stability is not a coincidence. It has been achieved through an extraordinary combination of state intervention, supply diversification, and financial absorption by public sector oil companies.

Interventions that come at a steep cost

Over the past few years, India has quietly built a more resilient energy architecture. The country expanded its sourcing basket beyond the Gulf, increased strategic reserves, and strengthened ties with suppliers in Russia, the United States, West Africa, and the Atlantic basin. Union Petroleum Minister Hardeep Singh Puri recently reiterated that India's crude supply position remains secure despite disruptions around the Strait of Hormuz, pointing to the country's growing ability to source oil from non-Gulf origins and maintain refinery throughput at high levels.

Taking advantage of the exit of the United Arab Emirates (UAE) from the Organization of the Petroleum Exporting Countries, India signed an agreement with the UAE to store 30 millions of crude oil in India's Strategic Petroleum Reserve. The government's response since the latest



Thiruvannathapuram S. Ramakrishnan

Public policy expert

escalation has been swift. Refineries were directed to maximise LPG production to meet rising domestic demand, especially given the dramatic expansion of cooking gas access under the Ujjwala scheme. LPG connections in India have risen from roughly 14.5 crore in 2014 to more than 33 crore today, fundamentally transforming household energy consumption patterns. Gas allocation was prioritised for households, public transport networks, and fertilizer plants to avoid cascading disruptions across essential sectors. Domestic LPG production was reportedly increased by nearly 50% during the peak of the crisis response, while all 25 fertilizer plants continued receiving around 70% of their gas requirements to maintain agricultural supply chains. Naval deployments in the Gulf of Oman, diplomatic engagement with multiple countries, and efforts to secure alternative shipping arrangements underline how seriously India has treated the crisis. These measures have bought the country valuable time. But they have also come at a steep cost.

Pressures on oil firms

India's state-run Oil Marketing Companies (OMC) are now operating under enormous financial stress, selling fuel below market-linked costs in order to protect consumers from inflationary shocks. Mr. Puri recently indicated that under-recoveries could rise sharply if elevated crude prices persist, with some estimates placing daily losses near ₹700 crore-₹800 crore during peak volatility. The government has already reduced excise duties and imposed temporary export restrictions on refined fuels to retain supplies within the domestic market.

This strategy may be politically prudent in the short term, but is economically difficult to sustain over a prolonged period. Energy subsidies of this scale eventually strain public finances, weaken the balance sheets of oil companies, and distort market signals that encourage efficient energy consumption.

The larger challenge is that India's vulnerability is structural, not temporary. Nearly every major sector of the economy – transport, logistics, aviation, manufacturing, agriculture, and fertilizers – remains heavily dependent on imported fossil fuels. Even if India succeeds in avoiding immediate shortages, it cannot remain permanently insulated from a prolonged global energy shock.

There are already signs that the government recognises this reality. Prime Minister Narendra Modi's appeals for responsible energy use – including reducing unnecessary travel, conserving fuel, and encouraging remote work where feasible – reflect an administration preparing the public for a period of prolonged uncertainty. Such messaging would have seemed extraordinary only a few years ago. Today, it

appears pragmatic. There is a strong argument for calibrated correction. India has managed inflation relatively effectively over the past decade compared to many major economies, creating some room for a measured increase in petroleum prices without triggering runaway inflation. Consumer Price Index inflation remained comparatively moderate in early 2026 – at around 3.2% to 3.5% through the first four months of the year – suggesting that limited price rationalisation may still be economically manageable. A gradual pass-through of global energy costs would reduce the fiscal burden on the state, stabilise oil marketing companies, and encourage more responsible consumption patterns.

For now, India has demonstrated remarkable agility in navigating one of the most serious energy disruptions in modern history. Supplies remain stable, panic has been avoided, and the government has managed to shield ordinary citizens from the worst immediate consequences.

The realities of a new energy era

But energy shocks of this scale eventually demand economic realism. The true cost of fuel cannot be deferred forever. India's challenge is no longer merely surviving the crisis; it is preparing the public and the economy for a world in which energy security will remain fragile, contested, and deeply political for years to come.

Recent reports suggest that Indian refiners continue to diversify sourcing aggressively even as global analysts warn that a prolonged Hormuz disruption could widen India's fiscal deficit and weaken the rupee. That should serve as a reminder that the situation is not a temporary headline cycle. It marks the beginning of a new energy era – one in which resilience, diversification, and conservation will matter as much as diplomacy itself. The government has raised petroleum product prices several times, cumulatively by about 7%. Yet, this piecemeal approach neither matches international crude oil prices adequately nor meaningfully reduces the burden on OMCs. Reports suggest that OMCs continue to incur losses of ₹700 crore to ₹800 crore a day, and that only an additional 13% hike, beyond the existing 7%, would eliminate these losses. It has also been reported that the government has returned to adjusting fuel prices in line with fluctuations in international crude oil prices. However, frequent revisions create uncertainty for consumers trying to manage household and business budgets. Instead of incremental increases, the government should implement a one-time price hike of at least 13% on petroleum products, including petrol, diesel, and aviation turbine fuel. Such a move, though difficult, would reduce uncertainty, stabilise OMC finances, and allow prices to remain steady until there is a significant shift in global crude prices.

The petro products price hike is too little and too late

The judiciary's role in complete justice

The Supreme Court is empowered under Article 142 to pass necessary orders to deliver complete justice where existing laws fail to provide a specific remedy. While this power acts as a 'constitutional safety valve', critics argue that it may lead to judicial encroachment upon the domain of the Executive or the Legislature

LETTER & SPIRIT

C.B.P. Srivastava

Another milestone in the direction of delivery of complete justice by the Supreme Court of India is its recent decision to elevate the Right to safe travel on National Highways as a fundamental right, declaring it an integral part of the Right to Life under Article 21 of the Constitution. The Court took *suo motu* cognisance of two road accidents in November 2025, which led to a loss of 34 lives and has issued wide-ranging directives. [In *Re: Phalodi Accident vs. National Highways Authority of India and Others* (2025)]. The Court has clearly held that safe, well-maintained, and motorable roads are no longer just a policy goal, but a constitutional obligation of the state. It is an alarming fact that while National Highways comprise only 2% of roads, they account for 30% of fatalities. In 2025, National Highways in India saw approximately 26,770 deaths in the first six months alone. The government aims to reduce road accidents by 50% by 2030 and to achieve this goal, it has adopted a strategy focusing on strengthening Education, Engineering (roads/vehicles), Enforcement, and Emergency Medical Service has been adopted. Despite fatalities on the National Highways decreasing by 11% compared to 2024, they still remain alarmingly high. These figures must have been a contributing factor in the Supreme Court's decision while exercising its inherent power under Article 142 of the Constitution which talks about complete justice.

Inherent power of the Supreme Court

The Supreme Court is the custodian of the Constitution. Hence, it has been given such powers which could be exercised where the law is silent or is found incapable of grievance redressal. Such powers are not conferred by statute but



The power to deliver complete justice is residuary in nature. SUSHIL KUMAR VERMA

are inherent to its role as the highest court, enabling it to go beyond strict procedural constraints to prevent injustice or abuse of process. Another condition to invoke Article 142 is a manifest error and non-exercise of it might lead to travesty of justice. The Supreme Court in *Delhi Judicial Service Association vs. State of Gujarat* (1991) has held that the power to do complete justice is entirely of different level and of a different quality. The Court further says that any restrictions contained in ordinary laws cannot act as limitation on the constitutional power of the Court.

The concept of complete justice

A pertinent question that comes to our mind is whether justice could ever be incomplete. If not, then why has the term 'complete justice' been incorporated into Clause (1) of Article 142 of the Constitution? Another question that may arise is whether High Courts may also deliver complete justice.

The power to deliver complete justice is residuary in nature and it may be exercised to ensure the observance of due

process of law. This is an extraordinary jurisdiction implicitly vested with trust and faith that it shall be exercised by applying the principle of natural justice, i.e., fairness. The Court also recognises its significance, and therefore, held in *Hitesh Bhatnagar vs. Deepa Bhatnagar* (2011) that extraordinary care and caution shall be observed while exercising this jurisdiction.

Article 142 empowers the Supreme Court to pass any necessary order to deliver comprehensive, equitable justice, even if existing laws or procedural technicalities do not provide a specific remedy. This power acts as a "constitutional safety valve" to fill legal gaps. It is a well-established fact that the Constitution of India gives precedence to natural justice over other forms of justice. In a landmark judgment, the apex court, in *Canara Bank vs. Debasis Das* (2003), says that the Constitution intends to deliver substantive justice, which is the removal of injustices and it shall be delivered either by way of legal or natural justice. In a situation where legal justice is incapable of doing so, the principles of

natural justice must be followed.

Complete justice and High Courts

The question of whether High Courts could also deliver complete justice may be answered on the basis of the Supreme Court's decision in *Anil Kumar Jain vs. Maya Jain* (2009) in which the Court held that the powers of High Courts under Article 226 of the Constitution are certainly not at par with those of the Supreme Court under Article 142. However, justice is a wide concept and shall always be complete. Thus, the High Courts may also deliver complete justice, though in a more circumscribed manner than the Supreme Court, whose inherent powers under Article 142 serve as one of the tools for applying the concept of due process of law in rapidly changing social, economic, political and value systems within and outside India.

Cause for controversy

The exercise of Article 142 is often criticised as judicial overreach that undermines the principle of separation of powers. Critics point out that the Court bypasses the established laws and procedures and may encroach upon the domain of the Executive or the Legislature. However, such criticisms do not have much rationale. It is true that invoking Article 142 makes the judiciary more active. However, judicial activism involves the proactive and progressive interpretation of laws or constitutional provisions. Its constitutional intent is to deliver justice, be it social, economic, political or legal. The problem arises when new and evolving social realities, such as live-in relationships or matters relating to homosexuality, emerge and established laws and procedures may prove inadequate to deliver justice. In such situations the Supreme Court, as the custodian of the Constitution needs to proactively take steps to ensure that complete justice is delivered. (C.B.P. Srivastava is President, Centre for Applied Research in Governance, Delhi)

THE GIST

▼
The Supreme Court of India, as the custodian of the Constitution, has been given such powers which could be exercised where the law is silent or is found incapable of grievance redressal.

▼
The Court's power to deliver complete justice is residuary in nature, and it may be exercised to ensure the observance of due process of law. It is an extraordinary jurisdiction implicitly vested with trust and faith that it shall be exercised by applying the principle of natural justice.